



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2003/पौष 2, 1925

No. 299]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2003/PAUSA 2, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2003

विषय:- चीन जन.गण., जापान, यूएसए और ईयू से माइका पर्ल पिगमेंट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच का आरंभ ।

सं. 14/22/2003-डीजीएडी.—मै. सनदर्शन केमिकल्स, पुणे ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन, जापान, यूएसए और ईयू मूल के अथवा वहां से निर्यातित माइका पर्ल पिगमेंट के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

1. विचाराधीन उत्पाद:

विचाराधीन उत्पाद 'धुतिमान/आभायुक्त/तुषारित प्रभाव, ऐसे मुक्ता रूपी प्रभाव, धात्वीय प्रभाव देने वाले कुछ अकार्बनिक पिगमेंट्स/कलरिंग एजेंट हैं जिन्हें बाजार में वाणिज्यिक रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड अथवा आयरन ऑक्साइड की सतहयुक्त पर्ल पिगमेंट अथवा पर्ल लस्टर पिगमेंट अथवा पर्ल पिगमेंट के रूप में जाना जाता है' । याचिका में उल्लिखित माइका पिगमेंट अथवा माइका पर्ल पिगमेंट शीर्ष 31206.11 और 3206.19 के अंतर्गत वर्गीकृत विचाराधीन उत्पाद है ।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति

याचिकाकर्ता देश में उत्पाद का अकेला उत्पादक है, इसलिए सकल भारतीय उत्पादनकर्ता है ।

3. शामिल देश/क्षेत्र

वर्तमान जांच में शामिल देश/क्षेत्र चीन पीआर, जापान, यूएसए और ईयू (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) हैं।

4. समान वस्तुएं

याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं चीन पीआर, जापान, यूएसए और ईयू के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुएं नियमों के अर्थों के भीतर संबद्ध देशों/क्षेत्र से आयातित वस्तुओं के समान समझी जा रही हैं।

5. पाटन और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य:- याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य का परिकलन या तो कुछ संबद्ध देशों के मामले में उपलब्ध कराई गई घरेलू कीमतों अथवा अन्य संबद्ध देशों के मामलों में सामान्य मूल्य की गणना से किया है।

निर्यात कीमत:- याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत का दावा आयात आंकड़ों, प्रविष्टि बिलों, गौण स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है।

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक है।

इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि चीन पीआर, जापान, यूएसए और ईयू में विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य उन कीमतों से बहुत अधिक है जिन पर इनका भारत को निर्यात किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह मालूम होता है कि संबद्ध वस्तुएं चीन, जापान, यूएसए और ईयू के निर्यातकों द्वारा पाटित की जा रही हैं।

6. क्षति और कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक सूचक जैसे उत्पादन, बिक्रियां, लाभ/हानि आदि से सामूहिक और संचयी रूप में यह मालूम होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

7. पाटनरोधी जांच का प्रारंभ

पूर्वोक्त पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों/क्षेत्र के मूल से अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारण करने के लिए पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

8. जांच अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2002 से 30 सितम्बर, 2003 तक (18 महीने) है।

9. सूचना प्रस्तुत करना

इस कार्य से संबंधित संबंध देशों/क्षेत्र में ज्ञात निर्यातकों और भारत में आयातकों को निर्धारित फॉर्म में ओर तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों की विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय पाटनरोधी निदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को जानकारी देने के लिए अलग-अलग पत्र लिखे जा रहे हैं। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी निम्न प्रकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित फॉर्म में ओर तरीके से जाँच से संबंधित अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

10. समय - सीमा

वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी सूचना इस प्रकार भेजी जानी चाहिए कि वह प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर पहुँच जाए। तथापि ज्ञात निर्यातकों और आयातकों जिन्हें अलग से लिखा जा रहा है, के लिए उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक है।

11. पाटनरोधी जाँच एक समयबद्ध कार्य होने के कारण यदि निर्धारित समय के भीतर उत्तर प्राप्त न हो अथवा किसी भी प्रकार से सूचना अपूर्ण हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त नियमों के अनुसार अपने जाँच परिणाम रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज कर सकता है।

12. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:-** नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार सार्वजनिक फाइल जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अंगोपनीय रूपांतर होगा, का निरीक्षण कर सकता है।

13. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार शामिल होने से अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जाँच में बाधा डालता है तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच निष्कर्ष रिकार्ड कर सकते हैं और ऐसी सिफारिशें जिन्हें वह उचित समझे, केन्द्र सरकार को कर सकते हैं।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2003

Subject: Initiation of anti-dumping investigations concerning imports of Mica Pearl Pigment from China PR, Japan, USA and EU.

No. 14/22/2003-DGAD.—M/s Sundarshan Chemicals, Pune, has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Mica Pearl Pigment

originating in or exported from China, Japan, USA and EU and has requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. Product Under Consideration:

The product under consideration is "certain inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/shinning/frosted effects, such pearlescent effects, metallic effects, commercially known in the market place as Titanium Dioxide or Iron Oxide coated Mica Pearl Pigment or Pearl Luster Pigments or Pearl Pigment". Mica Pigment or Mica Pearl Pigment stated in the petition is the product under consideration classified under the heads 3206.11 & 3206.19.

2. Domestic Industry Standing:

The petitioner is the sole producer of the product in the Country and, therefore, accounts for total Indian Production.

3. Country(ies)/ Territory Involved:

The countries/territory involved in the present investigations China PR, Japan, USA and EU (referred to as subject countries/territory hereinafter).

4. Like Goods:

The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from China PR, Japan, USA and EU. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries/territory within the meaning of the Rules.

5. Dumping and Dumping Margin:

Normal Value: The petitioner has computed the normal value either from the domestic prices made available in case of certain subject countries or constructed the normal value in case of other subject countries.

Export price: The petitioner has claimed export price based on the import figures, bills of entries, data received from the secondary sources and other facts available.

Considering the normal value and export price the dumping margins are significantly higher than the de-minimis limit.

There is sufficient evidence that the normal values of the product under consideration in the China PR, Japan, USA and EU are significantly higher than the prices at which it has been exported to India, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by the exporters from China, Japan, USA and EU.

6. Injury and Causal Link:

The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, profit/loss etc. collectively and cumulatively, indicates that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient prima facie evidence that the imports of the product under consideration have caused material injury to the domestic industry.

7. Initiation of Anti-Dumping Investigation:

In view of the foregoing paragraph, the Designated Authority initiates anti-dumping investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries/territory.

8. Period of Investigation:

The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April, 2002 to 30th September, 2003 (18 months).

9. Submission of Information: The exporters in the subject countries/territory and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate of Anti-Dumping, Udyog Bhavan, New-Delhi -110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

10. Time Limit: Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

11. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.

12. Inspection of Public File: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

13. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority